encouraging voluntary agencies and supporting their activities. And last but not the least is what we can do is—I suggest, Madam, that the House should have an occasion to look into my suggestion quite seriously —to constitute a Joint Committee of both the Houses on Social Legislation, and this Joint Committee should serve as a watchdog committee on the performance and implementation of the social legislation and to report to Parliament its deliberations. These reports should be annually placed on the Tables of both the Houses and should be discussed in both the Houses.

Now, Madam, I end by saying: let us all continue to build a society in which the age-old prejudices against the girl child disappear and we have truly an egalitarian society in which there is no discrimination against the child on the ground of sex.

Thank you.

4.00 P.M.

MOTION OF THANKS ON PRESIDENT'S ADDRESS

THE DEPUTY CHAIRMAN : Now we will takeup the Motion of Thanks on the President's Address. Shri Virendra Verma.

श्री वीरेन्द्र वर्मा (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं :—

कि राष्ट्रपति के प्रति निम्नलिखित रूप में कृतज्ञता ज्ञापित की जाये :—

"राष्ट्रपति ने 12 मार्च, 1990 को संसद की दोनों सभाओं की सम्मिलित बैठक में कृपया जो अभिभाषण दिया है, उसके लिये राज्य सभा के सदस्य, जो सभा के वर्तमान सत्र में उपस्थित हैं, राष्ट्रपति के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं।"

माननीय, लोकसभा के चुनाव से पूर्व देश में उच्च स्तर पर बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार दिनोंदिन बढ़ती आवश्यक वस्तुओं की महंगाई, अराजकता, साम्प्रदायिकता, मिलावट, बेरोजगारी और निरन्तर गिरती जा रही प्रशासनिक कुशलता ने जनता को कांग्रेस से और कांग्रेस की सरकार से निराश कर दिया था। लोक सभा के चुनाव में जनता ने अपनी नाराजगी प्रकट की। और कांग्रेस को इधर से उधर की तरफ़ बैठना पड़ा। 9 विधान सभा चुनावों में पांडिचेरी के चुनाव में कांग्रेस के नेताओं ने विशेषकर यह प्रचार करने का प्रयास किया कि जनता दल की सरकार या राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार जनता दल की—मैं गलत कह गया—नर्म है, कमजोर है और कमजोरी के साथ अपना कार्य कर रही है और पब्लिक को राष्ट्रीय मोर्चे के खिलाफ़ भड़काने की चेष्टा की, लेकिन इन 9 विधान सभाओं के चुनावों में जनता ने यह साबित कर दिया कि राष्ट्रीय मोर्चे की नीतियां और उसके कार्यक्रम सही हैं और कांग्रेस को फ़िर अपने मुंह की खानी पड़ी तथा एक दो राज्यों को छोड़कर प्रायः सभी राज्यों में राष्ट्रीय मोर्चे के समर्थक दलों की सरकारों का गठन हुआ।

2 दिसम्बर को राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार के प्रधान मंत्री ने शपथ ली। विरासत में हमें आपसे क्या मिला ? आपसे मतलब मेरा उपसभापति से नहीं है, बल्कि कांग्रेस की सरकार से है।

उपसभापति : आप कहिए "इनसे"।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : कांग्रेस की सरकार ने हमें विरासत में तीन चीजें मिली हैं, जलता हुआ जम्मू और काश्मीर, विस्फोटक पंजाब और रामजन्म भूमि तथा बाबरी मस्जिद की जटिल समस्या।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) : और खाली खजाना।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : और खालो खजाना। 4 चीजें हमें प्राप्त हुई हैं।

महोदया, जम्मू और काश्मीर में 1987 को मार्च में शायद नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस की मिली-जुली सरकार बनी। साल भर तक उसे ठीक काम करने की चेष्टा की। लेकिन गत दो वर्षों से उसकी निष्क्रियता और उसका नकारात्मक रूप देश के सामने, जम्मू काश्मीर की जनता के सामने है। मेरे से पूर्व इसी स्थान पर बैठे हुए देश के गृह मंत्री ने उन हालात पर विस्तार के साथ चर्चा की है जो हालात वहां हो चुके थे इसलिए मैं उनकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता लेकिन; महोदया, यह अवश्य बता देना चाहता हूं कि वहां के हालात बदतर हो चुके थे। वहां कोई प्रशासन नहीं रह गया था और वहां की मिली जुली सरकार कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेंस की आंख बंद किये, कान बंद किये अपने सामने राष्ट्रविरोधी शक्तियों को पनपते हुए देखती रही। राष्ट्रविरोधी शक्तियों ने क्या नहीं किया? चाहे मकबूल बट साहब का फांसी का दिन था या इंग्लैंड के सलमान रुश्दी ने जो किताब लिखी थी उसके खिलाफ जलूस था...

विपक्ष के नेता (श्री पी० शिव शंकर) : वाजपेयी जी आपको गलत रास्ते पर डाल रहे हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : सलमान रुश्दी ने किताब लिखी थी लंदन में, भारत सरकार ने उस पर पाबंदी लगायी और जम्मू और काश्मीर में उसके खिलाफ जलूस निकलता है और आग लगायी जाती है केन्द्रीय सरकार के दफ्तरों में, अकियतों के खिलाफ प्रचार किया जाता है और वह सरकार, आपकी मिली-जुली सरकार देखती रही और सुनती रही।

महोदया, सारी दुनिया में है कि जम्मू-काश्मीर की तरफ से पाकिस्तान ने प्रचार करवाया, ट्रेंड पर्सोनल इधर भेजे और जब उधर भारत सरकार द्वारा यह कहा गया कि शिमला समझौते के अनुसार, जिसके लिए आप वचनबद्ध हैं, आप कार्य करें, तो कहा कि वह 1972 का है। वह अभी आऊट आफ डेट हो गया है, उसकी अब अहमियत नहीं है और 1947 ई. का सुरक्षा परिषद् का प्रस्ताव, आज भी मान रखता है, जनमत संग्रह उसके अनुसार करवाया जाए, जब कि उस प्रस्ताव के प्रतिकूल क्रियायें पाकिस्तान निरंतर प्रारंभ से ही करता रहा है।

माननीय महोदया, मैं आपके माध्यम से इस सरकार की ओर से यह आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत को किसी का एक इंच लेने की इच्छा नहीं है और न अपने देश का एक इंच भी देने की इच्छा है।

माननीया, पंजाब में सन् 1982 ई. में अशांति प्रारंभ हुई, लूटमार भी चली, मेहता चौक में गोलियां चलीं, अटवाल डी.आई.जी. का कत्ल हुआ, कांग्रेस की सरकार क्या कर रही थी? इस कोशिश में थी कि अकाली दलों में फूट पड़ जाए। एक दल को अपने साथ लेकर के अकालियों की शक्ति को कमजोर करके अपनी शक्ति बनाई जाए और इसी कारण निरंतर सन् 1984 ई. तक आंख बंद किये हुए कांग्रेस बैठी रही। जून 1984 ई. में स्वर्ण मंदिर पर ब्लू स्टार आपरेशन हुआ। भारत का जवान भी मरा, वह तो देश की आजादी के लिए मरता ही है, देश के लिए मरता ही है। स्वर्ण मंदिर भी अपवित्र हुआ, बहुत सिख भी मरे। प्रतिक्रियास्वरूप देश के प्रधान मंत्री, तत्कालीन प्रधान मंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी जी का 31 अक्तूबर, को उनके निवास स्थान पर उनके गार्डों के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। ईश्वर न करे ऐसा कोई मामला हो जाए कभी, लेकिन कांग्रेस के आदमियों व सरकार को शर्म नहीं आई?

श्री राम चन्द्र विकल (उत्तर प्रदेश) : किस मामले में?

श्री वीरेन्द्र वर्मा : श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या उनके निवास स्थान पर उनके गार्डों के द्वारा की गई पर कांग्रेस वालों ने अपनी जिम्मेदारी का अहसास नहीं किया। विदेशों में तो सरकार के त्याग-पत्र हो जाते हैं, आप कहेंगे कि हो तो गया था त्याग-पत्र।

उसके बाद 31 अक्तूबर, 1, 2, 3 और 4 नवम्बर को क्या दिल्ली में हुआ और क्या देश में हुआ? कानपुर में, जबलपुर में, मेरठ में और अनेकों स्थानों पर नर-संहार हुआ। अकेले दिल्ली में तीन हजार से ज्यादा बेगुनाह आदमी मारे गये, उनका धन लूटा गया, अस्मतें लूटी गई, बेरमती की गई, क्या लिया है कोई एक्शन आपने आज तक?

एक कमेटी भी बनी थी। उसको भी रोक दिया गया, कोई एक्शन नहीं लिया गया।

1984 ई. में स्वर्ण मंदिर पर ब्लू स्टार आपरेशन के कारण और 31 अक्तूबर तथा 1, 2, और 3 नवम्बर को जो सिखों का नर-संहार हुआ, उससे केवल हिंदुस्तान का ही नहीं संसार का सिख भी कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के खिलाफ हो गया।

आप लोग बहुत नाराज हो रहे हैं कि जम्मू-काश्मीर के मुख्य मंत्री को हटा दिया। उन्हें हम ने नहीं हटाया, आप ने हटाया था सन् 1984 ईसवी में। इसी जगमोहन को जो आपका बहुत लाड़ला था, इसी के मार्फत आपने जम्मू-काश्मीर के मुख्य मंत्री को बर्खास्त कराया था सन् 1984 में। इसी गवर्नर ने जब यहां तुर्कमान गेट पर बुल्डोजर चलाए थे तब भी वह संजय गांधी का बड़ा लाड़ला डिप्टी चेयरमैन डी.डी.ए. में था। उसके बाद जब श्रीमती इंदिरा गांधी 1980 ईस्वी में प्रधान मंत्री बनीं तब इसे गोवा का गवर्नर बनाकर भेजा था। फिर गोवा से दिल्ली का गवर्नर बनाया उसके बाद उन्हें कामयाब और योग्य समझकर जम्मू-कश्मीर में गवर्नर बनाकर 1983-84 में भेजा और वहां भेजकर फारुख अब्दुल्ला की सरकार को बर्खास्त कराया। अब आप यह कहते हैं कि उनको गवर्नर क्यों बना दिया।

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव (महाराष्ट्र) : आपने भी वही किया।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : हमने आपके आदमी को गवर्नर बनाया। यह सोचते हुए कि वह योग्य आदमी है उसको आपने गोवा से हटाकर दिल्ली में रखा और योग्य समझकर जम्मू-काश्मीर में भेजा, हम ने भी उस की योग्यता का फायदा उठाने के लिए आपके आदमी को जम्मू-काश्मीर में राष्ट्रीय हित में भेजा।

श्रीमती सत्य बहिन (उत्तर प्रदेश) : फिर भी आपकी सरकार सोती रही ... **(व्यवधान)**...

श्री वीरेन्द्र वर्मा : सो हम कहां रहे थे, सो तो आप रहे थे। जनता ने बता दिया कि आप सो रहे थे।... **(व्यवधान)** यह 29 तारीख (मार्च) के चुनाव हो जाने दो, आपको पता चल जाएगा। यहां जितनी भी आप बड़बड़ करती हैं, आपको पता चल जाएगा।... **(व्यवधान)**

मान्यवर, चाहे पंजाब का मामला हो, चाहे जम्मू-काश्मीर का मामला हो, सारे मामलों में भारत की वर्तमान सरकार सह-अस्तित्व के आधार पर, बंधुत्व के आधार पर, शांति और प्रेम के आधार पर विश्वास स्थापित कर के वहां की जनता में आत्मीयता स्थापित कर के एक नई दिशा पैदा करना चाहती है। नए हालात पैदा करना चाहती है और नए हालात पैदा भी हुए हैं। अगर आप यह कहें कि साहब अब कत्ले आम पंजाब में ज्यादा हुआ है, यह आंकड़े मेरे पास मौजूद हैं। गृह मंत्रीजी ने भी आंकड़े दिए थे, वह भी मेरे पास मौजूद हैं। मान्यवर, पंजाब में दिसम्बर में 121 आदमी मरे, जनवरी, में 126 और फरवरी में 95 मरे। मगर सन् 1989 के आंकड़े पूरे मेरे पास नहीं हैं, तीन ही महीने के हैं। 1989 के तीन महीनों अक्तूबर, नवम्बर और दिसम्बर के 129,

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

128 और 149 हैं। इन से कम पंजाब में कत्ले आम हुआ है, जितना कि आपके जमाने में, सन् 1988 में हो रहा था।

मान्यवर, अभी आदरणीय बहिन जी बहुत जोर से कह रही थीं। बरनाला की सरकार सितम्बर, 1985 ईसवी में गठित हुई और 10 मई, 1987 ई० को आपने उनको बर्खास्त कर दिया। चलने देते हैं आप निर्वाचित सरकार को? आपने 10 मई, 1987 को बरखास्त किया था। याद होगा आप सभी मेम्बरों को, कि 12 फ़रवरी को भारत के राष्ट्रपति ने पंजाब के मुख्यमंत्री की मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की थी और फ़िर 10-11 मई को उनको बरखास्त कर दिया था और आपने यह कहकर बरखास्त किया था उनको, कि पंजाब की हालत बिगड़ती चली जा रही है। महोदया, यह मेरे पास आंकड़े मौजूद हैं—जनवरी में 24, फ़रवरी में 22, मार्च में 26, अप्रैल में 32 और जब उनको हटाया गया, आपकी सरकार आई तो उस समय 37, आगे के महीने में 42; आगे बढ़ते चले गए तो नवम्बर, 1987 में पंजाब में 88 और फ़िर दिसंबर में 83 हो गया। सन् 1987 के साल में तो यही हाल रहा, सन् 1988 में आपने रिकार्ड ही तोड़ दिया और फ़िर भी आप जिम्मेदारी महसूस नहीं करते। माननीया बहन जी, पर थमा नहीं जा रहा था, वह तो जनता ने आपको रोका, नहीं तो थम नहीं रहे थे। ... (**व्यवधान**)

महोदया, जहां तक रामजन्म भूमि और बाबरी मस्जिद का है। फ़रवरी, 1986 ईसवी में रामजन्म भूमि मंदिर का द्वार न्यायालय ने खोला था। मैं विरोधी दल नेता से यह पूछना चाहूंगा वह या उनके आदमी उत्तर देने की कृपा करें, कि जब फ़रवरी, 1986 ईसवी में मंदिर का दरवाजा पूजा के लिए खोला गया तो भारत सरकार के तात्कालिक गृह मंत्री ने पूरे सवा तीन साल बाद 15-16 मई, 1989 को रामजन्म भूमि और बाबरी मस्जिद के प्रश्न पर विरोधी दलों के नेताओं की मीटिंग क्यों बुलाई? क्योंकि चुनाव सामने आ गए थे, इसी वजह से न? अगर आपको रामजन्म-भूमि और बाबरी मस्जिद के प्रश्न को सुलझाना था तो जिस दिन मंदिर खुला था, उसी दिन कोशिश करके आपको उस मामले को उच्च-न्यायालय में भेजना चाहिए था। अब 15-16 मई, 1989 को मीटिंग करते हैं और जुलाई में उसे उच्च-न्यायालय में भेजते हैं। अगर आप सन् 1986 में ही इसे उच्च-न्यायालय में भेज देते तो आज तक उसका मामला तय हो जाता, उसका फ़ैसला भी हो जाता। लेकिन आप फ़ैसला नहीं कराना चाहते थे, आपका इरादा था पोलिटिकल केपिटल बनाने का, आप उसका राजनीतिक लाभ उठाना चाहते थे और इसीलिए आप इरादतन उसको खींचकर ले जाते रहे लंबे और हिंदुओं के वोट हासिल करने के लिए शिलान्यास कराया... (**व्यवधान**)

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव: हमने?... (**व्यवधान**)

श्री वीरेन्द्र वर्मा: जी हां, हिंदुओं के वोट हासिल करने के लिए शिलान्यास करने की आज्ञा प्रदान की।

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव: वर्मा जी, आप इतने सीनियर लीडर हैं, इतना तो असत्य मत बोलिए। शिलान्यास हमने नहीं किया।

श्री वीरेन्द्र वर्मा: मैंने आपको तो नहीं कहा। मेरा रिकार्ड देख लीजिएगा। मैंने कहा कि हिंदुओं की वोट हासिल करने के लिए शिलान्यास कराया, शिलान्यास की इजाजत दी और मुसलमानों के वोट हासिल करने के लिए निर्माण पर पाबंदी लगाई। जो इतनी चालाकी और चतुराई से काम करता है कि एक तरफ़ हिंदुओं की वोट लेना चाहता है और दूसरी तरफ़ मुसलमानों की वोट लेना चाहता है तो उसके लिए

दोनों की ही वोट नदारद हो गई, मेरे मित्रो। . . . (**व्यवधान**)

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : आप ज्यादा चालाक निकले।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : लेकिन मेरा कहना है कि चाहें पजाब का प्रश्न हो या जम्मू-कश्मीर का प्रश्न हो या फिर रामजन्म-भूमि और बाबरी मस्जिद का प्रश्न हो, तीनों ही राष्ट्रीय प्रश्न हैं, राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न हैं। मैं माननीय सदन के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि इन तीनों इस्यूज पर एक्सप्लायट करने वाली बातों को न करें, बल्कि देशहित में इन समस्याओं को सुलझाने में, हल कराने में आपस में मिलकर के सहयोग दें।. . .

मैंने कल जम्मू और कश्मीर के ऊपर पूरे भाषण सुने। रुबिया या जगमोहन! रुबिया से समस्या हल हो रही है, जगमोहन से समस्या हल हो रही है। हमने तो आपके लाडले को भेजा कि आपका लाडला है, हमने कहा कि एक-आध तो इनका भी रखो और इतना काबिल कि गोवा से दिल्ली में लाए और दिल्ली से जम्मू-कश्मीर में भेजा। हमने इरादतन आपके विश्वासपात्र को भेजा।

माननीया, इस राष्ट्र को गर्व है कि धर्मनिरपेक्षता के सिद्धान्त को इस देश ने स्वीकार किया है, लेकिन इस देश का दुर्भाग्य भी है कि देश की स्वतंत्रता के साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी धर्मनिरपेक्षता की बलि पर सबसे पहले चढ़े और सम्पूर्ण भारत के तीन करोड़ से भी अधिक हिन्दू, मुसलमान और सिख इस देश के बंटवारे के समय तबाह और बर्बाद हुए। हमारी जवान बहन और बेटियों की अस्मतें लुटीं। इतनी बड़ी तबाही, इतनी बड़ी कुर्बानी भी हिन्दुस्तान के कट्टरपंथियों की आंखों को न खोल सकी और यह इस देश का दुर्भाग्य है कि दोनों सम्प्रदायों मे कट्टरपंथिता बढ़ती चली जा रही है।

हमारी सरकार की यह चेष्टा है और रहेगी कि अल्पसंख्यकों को पूरी सुरक्षा प्रदान की जाए। जो 15 सूत्री कार्यक्रम है, जो कोल्ड स्टोरेज मे रखा है, रद्दी की टोकरी में पड़ा है, उस पर भी ईमानदारी के साथ अमल किया जाए और उर्दू जबान जो राष्ट्रीय भाषा है और मैंने भी पढ़ी है, मैं तो नहीं समझता कि अगर और भी पढ़ लें तो किसको आपत्ति होगी। हिन्दू भी पढ़ते हैं, मुसलमान भी पढ़ते हैं और सिख भी पढ़ते हैं। तो उर्दू भाषा को गुजरात समिति की रिपोर्ट के अनुसार बढ़ावा दिया जाएगा, इस बात को भी इस सरकार ने घोषणा की है।

मान्यवर, मैं अगर आपके माध्यम से अपने बुजुर्गों से, अपने साथियों से, अपने मित्रों से यह मालूम कर लूं कि जब आपका शासन था तो भागलपुर जैसा नरसंहार हुआ है क्या इस देश मे कहीं? 6 महीने तक लगातार नरसंहार चलता रहा मेरठ में? अंग्रेज की हुकूमत रही, 3 दिन 4 दिन और 6 दिन मे समाप्त हो गया, 6 महीने तक मेरठ में हिन्दू-मुस्लिम झगड़ा चलता रहा, सैंकड़ों आदमी मलियाना अहमदाबाद, इन्दौर, कोटा, हर प्रदेश के मारे गए। कांग्रेस की सरकार जिम्मेदार नहीं थी? उस जमाने की आपकी सरकार की कोई रिस्पांस्विलटी नहीं थी? क्यों यह नरसंहार हुए हैं? और आप बता दीजिए कि 100 दिन से यह सरकार है, आपने बहुत दोष देने की कोशिश की है, 100 दिन के अंदर एक स्थान पर भी हिन्दू-मुसलमान मे रायट नहीं हुआ! (**व्यवधान**) . . .

प्रो० चन्द्रेश पी० ठाकुर : बिहार) : जयपुर में।

श्री पी० शिवशंकर : बिहार मे होली के समय।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : कोई नही हुआ; आपस का, चुनाव का, जीत और हार का झगड़ा था।

मान्यवर, दुर्भाग्यवश देश को यूनिटरी गवर्नमेंट म राज्यों और केन्द्र में कुछ

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

अविश्वास सा उत्पन्न होने लगा था। सरकारिया कमीशन ने संस्तुति भी की थी, लेकिन फिर भी अन्तर्राज्यीय परिषदों के गठन करने पर आपकी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। यह सरकार निर्णय ले चुकी है कि अन्तर्राज्यीय परिषदों का गठन किया जाएगा ...

देश की तथा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर देश हित में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन भी यह सरकार करेगी। मान्यवर, पैसे की कमी है लेकिन देश की सुरक्षा की खातिर रक्षा के संसाधनों में एक पैसे की भी कमी न की जाएगी। हमारी फौजों को और हमारे जवानों को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। संसाधनों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं की जाएगी और अगर हिन्दुस्तान का कोई शत्रु बुरी निगाह से हमारी ओर देखता है--जैसे पाकिस्तान सबक ग्रहण कर चुका है--उसको सबक सिखाया जाएगा लेकिन हम न पाकिस्तान की, न संसार की, एक इंच भूमि तो क्या, सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं लेना चाहते लेकिन अगर कोई हमारी जमीन को छीनना चाहता है तो उसके लिए हमारे हिंदुस्तान की सेवाएं हर तरीके से तैयार हैं।

मान्यवर, समान रैंक के लिए समान पेंशन, यह प्रश्न हमारे जवानों की तरफ से उठाया जाता रहा है लेकिन उसे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया था। अब इस सरकार ने उसको सिद्धांत रूप में कार्यान्वित करने के लिए स्वीकार कर लिया है और उसको कार्यान्वित किया जाएगा।

हमारे देश ने लोकतांत्रिक व्यवस्था सौभाग्य से चुनी है। रशिया तो 70 साल बाद चुन रहा है लेकिन हमारे नेताओं ने लोकतांत्रिक व्यवस्था में आस्था और विश्वास रखते हुए बहुत पहले ही इसको स्वीकार किया था लेकिन लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में जो गुंडागर्दी हुई है... **(व्यवधान)**

श्री संतोष बागड़ोदिया (राजस्थान) : मेहम की चर्चा कीजिए ... **(व्यवधान)**

श्री वीरेन्द्र वर्मा : अमेठी की भी चर्चा करूंगा, मेहम की भी चर्चा करूंगा... **(व्यवधान)**

तो ये लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव हुए थे, इनमें कई सौ लोगों की मृत्यु हुई। सबसे अधिक लोगों की मृत्यु हुई है आपके बिहार राज्य के अंदर। वहां हमेशा यही होता रहा है। वहां हमेशा बूथ कैप्चरिंग होती रही है। इसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी जानते हैं, केंद्र की सरकार भी जानती है और इस देश का प्रत्येक नागरिक जानता है कि बिहार में चुनाव के समय क्या होता है... **(व्यवधान)**

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : 40 क्रिमिनल लोगों को टिकट किसने दिया है? आपके जनता दल ने दिया है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : मान्यवर, एक भी गलत आदमी को अगर हमारी पार्टी से टिकट दिया गया है तो वीरेन्द्र वर्मा आखिरी आदमी है किसी भी गंडे के पक्ष में, इसकी ताईद करने वाला।

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : हम वीरेन्द्र वर्मा पर कभी इलजाम नहीं लगाते। आप बहुत अच्छे आदमी हैं ... **(व्यवधान)**

श्री वीरेन्द्र वर्मा : मैं आपके खिलाफ ही तो कह रहा हूं। आपकी पार्टी ने बिहार में बहुत से गलत आदमियों को टिकट दिए हैं, दूसरी पार्टियों ने भी बहुतों को टिकट दिए हैं। यह लोक-तंत्र के अस्तित्व के लिए, डेमोक्रेसी के अस्तित्व के लिए खतरा है और इसी कारण हमारी सरकार ने चुनाव पद्धति में आमूल परिवर्तन करने और व्यापक सुधार लाने के लिए प्रख्यात राजनीतिक दलों और प्रख्यात तजुर्बेकार व्यक्तियों की एक कमेटी बनाई है। इसी सत्र के समाप्त होने तक उसकी ठोस रूपरेखा आपके सामने आ जाएगी।

जहां तक महिम में गलत हुआ, मैं स्वीकार करता हूं । लेकिन महिम के पहले अमेठी में जो हुआ उसे भी आप स्वीकार करते होंगे । गलती तो गलती है चाहे अमेठी में हो चाहे महिम में हो। इलैक्शन कमीशन ने महिम में दोबारा चुनाव के आदेश दिए । महिम के अंदर पोलिंग स्टेशनों पर रिपोल की आज्ञा दी थी । अमेठी में कितनों में हुआ था ?

श्री मुख्तियार सिंह मलिक (हरियाणा) : वर्मा जी, आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप तब कहां थे जब तुर्कमान गेट का मामला था । तब आप कहां कांग्रेस पार्टी के अन्दर बैठे थे । आज आप बातें बना रहे हैं ।

उपसभाध्यक्ष [डॉ० जी० विजय मोहन रेड्डी पीठासीन हुए]

श्री वीरेन्द्र वर्मा : हम तो तुर्कमान गेट वाले के हक में नहीं थे, न महिम के हक में हैं । आप जरा धैर्य रखो। जनता ने इतना बड़ा सबक दिया, फ़िर भी आप धैर्य नहीं रखते । जनता ने इतनी बड़ी ठोकर लगाई, फ़िर भी अक्ल नहीं आई ... **(व्यवधान)**

श्री पी० शिव शंकर : वर्मा जी आप वहां से यहां सरक गए हैं ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : उपसभापति महोदया की आज्ञा से सरकार । ... **(व्यवधान)**

मान्यवर, भ्रष्टाचार इस देश में दुर्भाग्य से बहुत बड़ी हद तक पहुंच चुका था। अंग्रेजों जमाने में भ्रष्टाचार नीचे से ऊपर को चलता था और ऊपर वाले उसको रोकते थे लेकिन इस जमाने में भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे को चलता है । आपकी सरकार ने लोकपाल विधेयक के लिए एक संयुक्त प्रवर समिति बनाई थी । मैं भी उस समिति का सदस्य था । उस समिति ने एक भी सूबा नहीं छोड़ा जिसमें वह नहीं गई हो । उसकी रिपोर्ट आने को थी तो उस समिति को आपने रद्द कर दिया । यह सरकार लोकपाल विधेयक इसी सत्र में पास करेगी और जिसमें हमने कोशिश की थी कि प्रधान मंत्री भी रखे जायें तो आप नहीं माने थे । लेकिन अब प्रधान मंत्री महोदय को भी लोकपाल विधेयक में रखा जाएगा ।

मान्यवर, तीन साल तक लगातार बोफ़ोर्स केस पर शोर मचता रहा । जवाब पर जवाब दोनों सदनों में दिए गए । दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति बनाई गई । पर नतीजा क्या निकला जून 1988 में हिन्दू में प्रकाशित हुई भ्रष्टाचार के बारे में और उसके लिए सी० बी० आई० के सुपुर्द की गई जांच के लिए लेकिन आज तक सी० बी० आई० उसके बारे में अपनी जांच नहीं दे सकी और जब से नई सरकार आई है, उसने सी० बी० आई० को कहा और उसने अपनी जांच पूरी कर ली और 14 आदमियों के खिलाफ़ केसेज भी कर दिए, स्विटरलैंड के अंदर 6 खातों को भी सील कर दिया और, मान्यवर, यह तो 64 करोड़ का मामला था, वहां तो एक ही खाते में 64 करोड़ है ... **(व्यवधान)**

कुछ माननीय सदस्य : नाम तो बता दीजिए । ... **(व्यवधान)**

श्री वीरेन्द्र वर्मा : सब पता चल जाएगा । अकेले बोफ़ोर्स नहीं, पनडुब्बी जिसके लिए टैलैक्स आया था जर्मनी से 30 करोड़ रुपए की जांच की जा रही है । वैस्टलैंड हैलीकोप्टर जिनके बारे में मैंने तथा कई अन्य माननीय सदस्यों ने इसी सदन में उठाया था कि वैस्टलैंड हैलीकोप्टर के खरीद के बारे में जांच हो, उसकी भी जांच हो रही है । सुमीतोमो कारपोरेशन जिसके जरिए ओ० एन० जी० सी० का एग्रीमेंट हुआ था ...

साढ़े छः करोड़ रुपया लन्दन में ललित सूरी गैराज ने, उनकी घर वाली ने, जमा किए हुए हैं । उसका भी मामला प्रकाश में आ जाएगा और 2500 करोड़ रुपए की जो खरीदारी हुई है ए-320 एयर बस की जिसमें अभी बंगलोर में आदमी मरे हैं उसकी भी जांच हो आपके सामने शीघ्र ही प्रकाशित हो जाएगी । हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेज

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

की नियुक्तियों और उनके स्थानान्तरण के लिए एक न्यायिक आयोग बैठाया जाएगा। इन नियुक्तियों को राजनैतिक स्तर पर न करके न्यायिक आयोग की संस्तुतियों के अनुसार किया जाएगा और उनका स्थानान्तरण भी।

रेडियो और टेलीविजन को स्वायत्तता की बात है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जो मेरे बड़े परम मित्र हैं, शिकायत कर रहे थे कि रेडियो का दुरुपयोग हो रहा है। कोई और कहे तो बात है लेकिन कांग्रेस के लोगों को रेडियो का दुरुपयोग और टेलीविजन के दुरुपयोग की चर्चा नहीं करनी चाहिए। हमने बंद कर दिया था रेडियो और टेलीविजन सुनना उस जमाने में जब कि आपकी हुकूमत थी।

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : आप टेलीविजन के अटोनोमी की बात करते है लेकिन जब टेलीविजन को देखते हैं तो लगता है अटोनोमी बिल्कुल गलत बात है। **(व्यवधान)**

श्री वीरेन्द्र वर्मा : हम और तुम बाहर बात कर लेंगे। नागरिकों की गोपनीयता में हस्तक्षेप करने के लिए डाकघर कानून में आपने संशोधन किया था। उसका हमने उस समय विरोध किया था। सौभाग्य से यह सरकार उसे वापस करा लायी है। पुनः उस पर विचार होगा। उस समय आपकी मैजोरिटी भी नहीं रहेगी। सूचना प्राप्त करने के अधिकार को भी गारन्टी दी जाएगी जिस पर आपने प्रतिबंध लगा दिया था।

श्रीमती मारग्रेट आल्वा (कर्नाटक) : सरकार बदल गयी है। आप अपनी सरकार के बारे में बोलिए। आप हमारे बारे में बोल रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री वीरेन्द्र वर्मा : अभी तो पांच साल तक आपको सुनना होगा। धैर्य रखना होगा।

श्रीमती मारग्रेट आल्वा : आप क्या करने वाले हैं, आप बताइए। हमारे बारे में क्यों कहते हैं। **(व्यवधान)**

श्री वीरेन्द्र वर्मा : 1989-90 में देश की अर्थ-व्यवस्था में अत्यधिक गिरावट आयी है। जिस दिन नयी सरकार ने भार संभाला तो 13 हजार 790 करोड़ रुपए का घाटा था। वित्त मंत्री महोदय ने जब बजट रखा था तो उस समय 7 हजार 300 करोड़ रुपए के घाटे को दर्शाया गया था कि इतना घाटा होगा। करीब-करीब दुगुना यानी 13 हजार 390 करोड़ का घाटा बन गया है। आयात-निर्यात का संतुलन बिल्कुल बिगड़ गया था। बाहरी और अंदरूनी ऋण ने हिन्दुस्तान के लोगों की कमर तोड़ दी। इन ऋणों से हिन्दुस्तान की कमर टूटी पड़ी है। भले ही दिल्ली वाले राजी हो रहे हैं। उस ऋण की अदायगी में वर्तमान प्रधान मंत्री कह रहे हैं कि उनके जमाने में 15 फ़ीसदी ऋण की अदायगी में देना होता था और अब 30 फ़ीसदी उसकी अदायगी में देना पड़ेगा जो आमदनी होगी निर्यात के जरिए।

जहां तक भाव का मामला है, चावल और गेहूँ और चीनी, इन सब के बारे में माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि सितम्बर और नवम्बर में 13 और 14 रुपए चीनी का भाव हो गया था और आज यह साढ़े सात और 8 रुपए के करीब है, और सब जगह मिलती है।

श्री जगेश देसाई (महाराष्ट्र) : कहां मिलती है?

श्री वीरेन्द्र वर्मा : आप ये बातें अपने भाषण में कहिए। चावल, गेहूं, और चीनी के भाव गिरे हैं।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया (बिहार) : किस दुकान पर मिलते हैं, जरा बता दीजिए।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : पांच साल तक आपको सुनना पड़ेगा। मैं आपको दिला

दूंगा । आप मेरे से मांगिए । चावल, चीनी, गेहूँ और चाय की कीमतों में पहले की तुलना में गिरावट आई है । मौजूदा सरकार आत्मनिर्भरता के आधार पर अपनी अर्थव्यवस्था को बनाने और उसको कायम करने और उस पर चलने पर विचार कर रही है । योजना आयोग का पुनर्गठन किया गया है । उत्पादक रोजगार लोगों को मिले, उससे गरीबी दूर हो, इस पर यह सरकार चलना चाहती है । रुपया बांटने से गरीबी दूर नहीं होती । भारत के पूर्व प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी ने स्वयं यह कहा था कि जितना रुपया हम आई० आर० डी० पी०, डी० आर० डी० ए० और दूसरी योजनाओं में बांटते हैं उसका केवल 15 फीसदी लाभार्थी व्यक्ति तक पहुंच पाता है । यह मैंने नहीं कहा है, तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी ने कहा है ... **(व्यवधान)** प्रधानमंत्री सारे देश के लिए बोलते हैं । उन्होंने यह बात कही थी.. **(व्यवधान)** । अभी आपको बहुत दिनों तक सुनना पड़ेगा । ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के निरन्तर बढ़ते हुए आर्थिक असंतुलन को दूर किया जाएगा । महिलाओं के आर्थिक विकास की तरफ विशेष ध्यान दिया जाएगा । समाज में इनको सम्मान मिले, इसके लिए प्रयास किया जाएगा । मेरी पांच-छः बहिनें यहां पर बैठी हुई हैं । हम तो उनका आदर करते हैं, लेकिन वहां से एक महिला का अनादर किया गया था । महिलाओं के सम्मान के लिए, समाज में उनको प्रतिष्ठा देने के लिए एक आयोग बनाया जाएगा ।

मैं अपनी बात कहने में नाकामयाब रहूंगा, अगर मैं किसानों के बाबत कुछ न कहूं । हमारे देश की अर्थ व्यवस्था कृषि पर आधारित है । पहली पंचवर्षीय योजना में साढ़े 37 फीसदी खर्च कृषि के लिए निर्धारित किया गया था । इसका विस्तार बढ़ता गया । लेकिन सातवीं पंचवर्षीय योजना में केवल 21 प्रतिशत कृषि के लिए निर्धारित किया गया । पहली योजना में तो साढ़े 37 प्रतिशत और सातवीं योजना में 21 प्रतिशत रखा है और इस सरकार ने निर्धारित किया है 50 फीसदी कृषि पर और ग्रामीण विकास के ऊपर ।

माननीय, टर्म्स आफ ट्रेड, कृषि और व्यापार की स्थिति बिलकुल बिगड़ी पड़ी है और वह किसानों के खिलाफ जाती है । जिसको कहते हैं प्राइजस रिसीव्ड एंड प्राइस पेड । किसान को उसकी पैदावार का क्या मिला और किसान को अपनी आवश्यकता की वस्तुओं के लिए क्या देना पड़ा । इसमें निरंतर अंतर बढ़ता चला जा रहा है । इस सरकार की यह चेष्टा होगी कि टर्म्स आफ ट्रेड किसानों के पक्ष में जाए, यह उनके विपरीत न रहे । दस हजार रुपए तक का ऋण लघु कृषकों, सीमांत कृषकों, बुनकरों, दस्तकारों, मजदूरों, गरीब आदमियों का समाप्त करने की घोषणा भी 19 तारीख के बजट में पेश की जाएगी ! . . . **(व्यवधान)** . . धैर्य रखें और मेरी बात सुनने की चेष्टा और कोशिश करें ।

माननीय, हमारा देश गांवों में रहता है । आज गांवों में पढ़ा लिखा आदमी भी बेकार है और गांवों में कोई उद्योग भी नहीं हैं । हमारी सरकार की यह चेष्ठा और कोशिश होगी कि लघु-स्तरीय तथा कृषि पर आधारित उद्योग जिनसे ग्रामीण लोगों को रोजगार मिले और उनकी आय मे वृद्धि हो, उनको गांवों मे स्थापित किया जाय । 1976 में मैं इनके साथ तो नहीं था, श्री मुख्तियार सिंह मलिक के साथ, वे जनसंघ में थे लेकिन मैं उनके साथ था ... **(व्यवधान)** ... कुछ तो सुन लीजिए ।

1976 मे बीस-सूत्री कार्यक्रम बना और उस बीस-सूत्री कार्यक्रम में श्रमिको को प्रबंध मे हिस्सेदारी का भी एक आइटम था कि हम मैनेजमेंट में, प्रबंध में श्रमिकों को भी हिस्सा देंगे । 1976 से अब तक 14-15 साल से यह रद्दी की टोकरी मे पड़ा रहा । इस सरकार की कोशिश है, इस सरकार का इरादा है कि श्रमिकों को उद्योगों में प्रबंध में भागीदार बनाया जाय, यह सूचना भी मैं आपको देना चाहता हूं ।

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

जहां तक सार्वजनिक उद्योगों का सवाल है उनकी हालत भी अच्छी नहीं है। इस देश में सार्वजनिक उद्योगों पर दौलत तो बहुत लगी हुई है लेकिन उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। हमारी सरकार एक श्वेत पत्र इसके ऊपर प्रकाशित करेगी और उनको जनता के प्रति जवाबदेह बनाएगी उन सभी उद्योगों को जनता के सामने जवाब देना होगा। काम करने का अधिकार संविधान में सम्मिलित किया जा रहा है। मैं अपने माननीय मित्रों से प्रार्थना करूंगा कि इसके लिए एजीटेशन करने की आपको जरूरत नहीं है कि काम के अधिकार का जो आपने वायदा किया था उसको पूरा किया जाय। बगैर आपके एजीटेशन के काम का अधिकार आपके सहयोग से संविधान में संशोधन करके किया जाएगा। .... **(व्यवधान)** . .

मान्यवर, इस देश में 25 फीसदी शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स की आबादी है। यह गरीब वर्ग है। इस सरकार से सबसे पहले कदम उठाया है कि जो नव-बौद्ध हैं उनको भी वही अधिकार और सुविधायें दी जाएगी, जो दूसरे हरिजनों को दी जाती है। लगातार 40 सालों से इस तरह की सुविधा आप इन गरीब आदमियों को नहीं दे सके। इसके लिये कानून बनाकर लागू किया जायेगा।

मान्यवर 360 करोड़ रुपये भोपाल त्रासदी के लिए सरकार ने अनुदानस्वरूप, सहायतास्वरूप वहां के लोगों को दिये हैं। **(व्यवधान)** . . .

मान्यवर, मेरे मित्र जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे, पैदा भी नही हुए होंगे। सन 1953 में काका साहब कालेलकर ने पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए अपनी रिपोर्ट दी थी। ढूंढ कर भी उस रिपोर्ट को मुश्किल से निकाला जा सकता है, रद्दी की टोकरी में कहीं दबी पड़ी होगी। क्यों दबी पड़ी रही, कौन जिम्मेदार है? जनता सरकार ने उस में सुधार करने की दृष्टि से मंडल आयोग को स्थापित किया। शायद 8 साल से ज्यादा तो हो ही गये होंगे मंडल आयोग की रिपोर्ट को आए हुए। वह रिपोर्ट भी रद्दी की टोकरी में पड़ी रही। इस सरकार का इरादा है, एक कमेटी भी बना दी है और इसी सत्र में इस संबंध में हम अपनी कार्यवाही से दोनों सदनों को अवगत भी कराएंगे।

मान्यवर, विदेश नीति, संसार में भारत की विदेश नीति खरी उतरी है। संसार के सभी देशों से हम शान्ति, प्रेम, सहअस्तित्व, गुटनिरपेक्षता के आधार पर अपनी कार्यवाही करने की चेष्टा करते हैं। हमारे सभी देशों से सम्बन्ध अच्छे हैं। हमने संबंध अच्छे बनाने की पाकिस्तान से भी लगातार इन चार दशकों में कोशिश की है लेकिन पाकिस्तान नफरत के आधार पर कायम हुआ था और नफरत के आधार पर पाकिस्तान बना और नफरत के आधार पर पाकिस्तान कायम है। हिन्दुस्तान के खिलाफ केवल मजहब के नाम पर, नफरत का प्रचार करता रहता है। मान्यवर, अफगानिस्तान हो चाहे संसार के दूसरे मुस्लिम राष्ट्र हों, संसार का कोई भी देश हो, हमारे सभी देशों से संबंध अच्छे हैं। रूस के साथ हम अपने सम्बन्धों पर गर्व कर सकते हैं। जिस तरह से हमारी विदेश नीति कसौटी पर खरी और पूरी उतरी है उसी तरह से हिन्दुस्तान और रूस की मित्रता भी खरी उतरी है। हमारे व्यापारिक सम्बन्ध अमरीका से सब से अधिक हैं। उनकी जो टेक्नीकल एडवाइस है उसका भी हम बहुत बड़ा लाभ उठा रहे हैं। हमारी किसी से भी शत्रुता नहीं है। शत्रुता हम पाकिस्तान से भी नहीं मानते हैं लेकिन पाकिस्तान हम से जरूर हृदय में शत्रुता रखता है। उसका सबक तीन दफा भारत के जवानों ने सेना के बहादुर सैनिक उसे सिखा भी चुके हैं। अवसर और मौका परमात्मा न दे, हम नहीं चाहते हैं कभी भी किसी से लड़ना, अगर ऐसा कभी हुआ तो फिर हमारे नौजवान उसको सबक सिखाने के लिए हमेशा तैयार हैं।

हमें अत्यधिक खुशी है कि 70 वर्ष साऊथ अफ्रीका के कब्जे में रहने के बाद

नामीबिया 21 मार्च को स्वतंत्र हो रहा है । भारत की सरकार निरन्तर कोशिश करती रही, अकेले नामीबिया के लिए ही नहीं बल्कि संसार के सभी कोलोनियल देश जो भी दबे पड़े थे उनकी आजादी के लिए निरन्तर कोशिश करता रहा । नामीबिया के लिए भी कोशिश करती रही । हमें बड़े भारी खुशी है कि नामीबिया स्वतंत्र हो रहा है और भारत के प्रधानमंत्री 21 मार्च को उनके इस जश्न में उत्सव में सम्मिलित होने के लिए वहां पहुंच रहे हैं । साऊथ अफ्रीका के यह भी खुशी का मौका है कि, डा. नेल्सन मंडेला रिहा हो गये हैं । हिन्दुस्तान में आजादी हासिल करने के लिए लोगों ने कुर्बानी दी है, हिन्दुस्तान के भी बहुत से नेता जेलों में हैं लेकिन नेल्सन मंडेला की कुर्बानी नहीं दी । 27 वर्ष तक उन जालिमों के जेलों में रहे जो अब रिहा हुए हैं । हमें यह आशा है कि साऊथ अफ्रीका भी स्वतंत्रता उस मायने में हासिल करेगा कि वहां के बहुसंख्यक लोगों को वोट का अधिकार हो और उनको उनकी सरकार प्राप्त हो ।

इस बात की वहां भी चेष्टा और कोशिश की जा रही है । एक दो बातें और कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

परिवार कल्याण पर सरकार का विशेष ध्यान है । यहां जितना भी विकास का काम होता है, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण वह दिखाई नहीं देता है । मेरे पास आंकड़े भी मौजूद हैं कि सन 1951 में जब पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई तो हमारी वृद्धि दर क्या थी पापुलेशन की और परिवार नियोजन पर अरबों रुपये खर्च करने के बाद हमारी जनसंख्या की वृद्धि का प्रतिशत क्या है । आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि सन 1951 से ज्यादा ही है कम नहीं है । मान्यवर, इन परिवार योजनाओं का देहातों में सही प्रसार भी नहीं हुआ है । देहातों में गरीब आदमी हैं, रोजगार भी नहीं है । दवाइयां भी देहातों की डिस्पेंसरीज में नहीं हैं, डाक्टर्स भी वहां नहीं जाना चाहते हैं । मैं अपने मंत्री महोदय से यह प्रार्थना जरूर करूंगा कि देहातों में परिवार कल्याण के कार्यक्रम को सफलता-पूर्वक चलाने में विशेष ध्यान दें । दवाइयों को भी मुहैया कराने की कृपा करें ।

मान्यवर, युवा वर्ग देश की शक्ति है भविष्य की आशा है । हमारा युवा वर्ग बड़े बड़े पदों पर नहीं आता । आई ए० एस०, आई०पी एस०, आई०एफ एस०, फारेन सर्विसेज में या दूसरी सर्विसेज में शहर का आदमी आता है । देर में वह पढ़ना प्रारम्भ करता है अतः इस सरकार ने उनकी कठिनाइयों का आभास करते हुए 26 साल से उनकी आयु बढ़ाकर 28 वर्ष की है । एक दफा पहले भी यह हो चुका था । माफ करेंगे, मेरे मित्र हैं जगेश्वर भाई जी, 28 वर्ष कर दी थी लेकिन इन्होंने वापस ले ली थी । इस सरकार ने 28 वर्ष कर दी है, यह कायम रहेगी, इसको कायम रखने की चेष्टा करेंगे जिससे कि गांवों में रहने वाले लोगों को उच्च पदों की परीक्षाओं में बैठने और उन्नति तथा तरक्की करने के साधन उपलब्ध हो सकें ।

मान्यवर, वर्तमान सरकार के सामने अनेकों गम्भीर चुनौतियां हैं किंतु देश की जनता और आप जितने भी बैठे हैं—ये तो सारे खाली पड़े हैं—आप सभी के सहयोग से उन चुनौतीपूर्ण समस्याओं का सामना करने में यह सरकार सफल होगी । इन शब्दों के साथ मुझे विश्वास है कि जो भाषण राष्ट्रपति जी ने 12 तारीख को दोनों सदनों को दिया है, उसके प्रति यह हाउस कृतज्ञता-पूर्वक अनुगृहीत रहेगा और उनको धन्यवाद देगा । जयहिंद ।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY) : Shrj N. E. Balaram to make his speech seconding the Motion.

5.00 P.M.

SHRI N.E. BALARAM (Kerala).: Mr. Vice-Chairman, Sir, this time we are discussing the problems of our country afer holding elections in a number of Assemblies. Now I think the political picture cf the country is very clear. Not only that, \ think the verdict ofthe people is also very clear. What they want to baveisachange,notonlyz change of party op parties, not only a

[Shri N. E. Balaram] change of government, but wita* they are more interested in is a change in policies- If one looks into the speech made by the President, one can see that there are a number of indications that this Government is going to follow a number of new policies. They want a change in the policies. I am not saying that it is an easy matter. I do not think so. Because they have already inherited a number of problems which are very serious problems which will take time, which need the cooperation of all sections of the people, of all partie,, to find a solution. I do not think those problems can be solved over-night

As 1 said, there are a number of problems which they have inherited. A set of problems is those which have been unleashed by the forces of communalism, fundamental i and secessionism. of course, yesterday and today, we have been discussing them sufficiently. Though there are a number of a n s approaches, the entire House is one on trie question of how to tackle gome of these problems, especially the problem of Kashmir. Tomorrow or day after, we are going to discuss the problem of Punjab. The problem of communalism will algo be com'ng up in the coming days- 1 am not taking much time on any of these problems, but (hese are very important problems which require the cooperation of all sections of the people of the country, of all parties and groups.

Here, 1 would say, what I find is that this Government has got a specific approach wtiich I could not find in the previous Government. I am not utilising this opportunity to criticise the previous Government. 1 am only saying what is new in their approach. There is something new, according to me. They are openly sharing— especially the Prime Mirister—tbeir views j with al) the parties- "hey are sharng their views with us, shar'ng their views with the Opposition part"es. They are listening to the op'rrons, criticisms and suggestions from all these parties and they are mak'ng a search for a national consensus on a number of important problems- This "s s,ometh'ng new in this country which did not see in the past, with the result that, I think, the poli+ical atmosphere is a little bit relaxed and the atmosphere here is legs oppressive. As some historians had done" in the pas*, they started the idea of assessing a hundred days' performance. Hundred days of Napoleon—tnat was the first h'stor'cal assessment of hundred days. I do not know why we are getting such a method here.

Now, here also we are seeing that assessment of 100 days. Even 'f we assess these 100 days of activities of this Government— I am not saying that all the activities of the Government are carried out—but, if you objectively assess the activities of the Government, you can &ee that it has an approach of finding solutions to the problems of the country on the basis of national consensus. Not only that. They want to resurrect the old, nationally accepted policies- That also they are doing. 1 think my friends will a^o agree with me that more and more consultations, meaningful consultations— not consultation for consultation's sake but meaningful consultation—sharing of views with the Opposition parties, and loud th'nkmg along with the Oppostion partes, makes a dent to reach a nat-'onal consensus on a number of issues- That is the way in which this Government is functioning. I fully support that sort of an approach. And that is why we were able to form a committee on the question of Kashmir. On a number of issues, in the future also the Government may follow the same policy and even be able to find consen-us on. most ofthe issues.

Naturally, a question will arise- why this attempt to reach a consensus policy now? The policy of consensus, according to me, is not a policy of convenience, not a policy of pragmatism nor a policy of opportunism. It is not even a tactical device to get out of some impossible impasse. I don't think go. This policy has arisen out of the objective conditions of this country and the attitude of the Government. it is out of the objective situation in the country and the subjective response on the part of the Government that this policy has ari sen because there are a number of issues to be tackled. In the past it was a one-man rule. It was not a party rule in the past. I don't think that Opposition party itself will agree that it was a party rule. It was a one -man rule and that one-man rule was taking a position of confrontation. They were not following a policy of consensus or conciliation or discussion or debate, and they were not trying to understand the view points of others. They were following a policy of confrontation on many occasions. Sometimes they challenged the entire democratic opinion of this country and that is why they were forced to withdraw the Bill of Defamation. I remember those occasions. If you look at the whole past history of the previous Government, it was a period of confrontation. Fortunately, that period of confrontation is over and I pray that that period of confrontation should never come up in the country again. We should not allow the policy of confrontation to rai se it s head again in thi s country.

What we want is a policy of national consensus to solve the problems. I think this policy will bear fruit. This policy can solve a number of problems. So, this is one thing I have found in the new Government. The same thing I have seen in the President's Address also. The approach of the entire Address shows that they want a policy of consensus. Somebody I was saying that there are parties I with opposition supporting the ! Government. I don't think my j friend, Mr. Vajpayee, will deny it.

Of course, we are supporting. ' The parties which have got opposite I views, are supporting this Govern- i ment. As I said, the basis is that all of us are trying to find out solutions on the basis of consensus, and the Prime Minister is keen, very keen—that is a very big thing— ¡ to share his views with others. That is a new thing that I have I seen, a new situation has come about. I think, this Government will continue with this policy, and that is very much represented by the speech made by the President. I said that we have inherited a number of problems. One type of problems I have already mentioned. I do not want to go into them. Again and again we have been discussing them, and we will discuss them again, the problems of communalism, Kashmir, Punjab etc. But now we are facing another set of problems. Unfortunately— I say "unfortunately"—somehow an impression has been created in the minds of people in some of our ! neighbouring countries. I am not saying, "All the neighbouring countries." Some doubts have been created that India is playing a big ■ brother role. Such doubts have been created in the minds of some of our neighbouring countries. I am not talking of all the countries, especially Pakistan, but some other countries, for instance, Nepal, Sri Lanka. Because of the activities of the previous Government an impression has been created that this country is playing the role of a big brother. Slowly this Government is trying to remove those doubts. Fortunately, this Government is trying to remove those impressions. I think this is a right thing that they are doing, they are moving in the right direction. We should not create doubts in the minds of the people ⌈ of our neighbouring countries that we are behaving like a big brother

[Shr* N. E. Balaram] We want co-operation of all the countries, especially the South Asia countries and we should use the SAARC as an instrument for that. We should try to erase the impression which has been created during the previous regime. It should be removed. There also we want an open policy, the same approach.

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry) : Replacing Governors is the new direction.

SHRI V. GOPALSAMY (Tamil Nadu) : He is speaking on external affairs, and you are speaking on Governors.

SHRI N. E. BALARAM : I am not speaking on black money question. I know what it is and how it spoiled young men also. I don't want to discuss about that.

SHRI V. GOPALSAMY : He is talking about our relationship with our neighbouring countries.

SHRI N. E. BALARAM : I am talking about the impression created by the Rajiv Government in the minds of so many neighbouring countries that India is behaving like a big brother in spite of our saying that we are adopting a policy of non-alignment etc. etc. The result is, doubts are there in the minds of other countries. This Government is slowly removing that impression. They are not standing on prestige. They are negotiating with all the countries. They are negotiating with Nepal. They are negotiating with Sri Lanka. I hope the Government will do so even on the question of talking with Pakistan. Don't forget the people of Pakistan. Pakistan is totally controlled by a section of anti-Indian groups. There are a number of democratic sections in Pakistan. You should not forget that once it was a part of this great land. That tradition is there. Don't forget that tradition though the division has taken place. So, on that question the Government should take a bold initiative. In spite of the difficulties, in spite of the belligerent attitude, India should take a bold initiative on the basis of the new Approach that it is adopting now. These are the second set of problems facing our country, to which out Government is applying its mind.

There is another set of problems. They are very difficult problems.

When the previous Government was there, there were a number of new policies. There were about thirteen new policies—'the new economic policy, the new textile policy, the new tax policy, the new education policy, the new export and import policy. My God, how many new policies were there! But what did the people say? I don't know whether the Congress Party has taken stock of the election results. So far I have not read anything about it. That is their business. But I do not ask the Congress party to have self-critical analysis of its own defeat. That is their own business. But I want them also to know that the people have already rejected almost all their policies. They want a new policy. That is the verdict. The verdict has some meaning, whether they like it or not, on all sorts of your new policies.

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE (Maharashtra) : You should talk about the verdict in Kerala.

SHRI N. E. BALARAM : The verdict in Kerala about the elections'? One of your stronghold seats was lost. That is what you are talking of as verdict. The verdict is there. They did not analyse the meaning of the verdict. Instead of having an objective analysis there was a whispering going on that within three or four months this Government was going to fall. Their first question was who would be the

Prime Minister. How many people want to become the Prime Minister ? They were raising such questions. Who would be the Prime Minister? The Prime Minister was elected. Now, I think they require a thorough study about their own defeat. It is a big defeat of your own policies and methods. You must accept this. This mistake should not be repeated on the part of this side. I am not going into the details of all the policies. At the time of the Budget debate I may, but for the moment I want to speak on one or two policies. What was the new economic policy? I want to know what was the net result of your new economic policy. We are facing very difficult fiscal crises, debt crises, balance of payments difficulties and a number of other difficulties. Our economy is not very healthy now. I think no economist will disagree with me on that. In spite of all the tall claims, as the President in his speech said last year that the agricultural production had slowed down, the industrial production had slowed down. Why? What happened to this new economic policy ? The net result of the new economic policy was to produce more durable consumer goods for the rich and upper class and they adopted all the anti-poverty programmes for the poor people. Those were the political and economic lines which you were following.

PROF. CHANDRESH P. THAKUR (Bihar) : What about the foodgrains production to the tune of 175 million tonnes ?

SHRI N. E. BALARAM : I agree with you on that. You study that report. What did it say ? It talked about food production. I agree some production is there. I don't deny that fact, but does that alone show the sound health of the economy ? Would you argue like that ? I don't think. I should not deny that there is some improvement on the economic front.

PROF. CHANDRESH P. THAKUR : My friend, Shri Balaram, is a very learned person. In his emotional outburst he is ignoring the fact that 175 million tonnes of foodgrains production is for the benefit of the poor people.

He also must realise—if he has forgotten he should remember that—as income grows, people eat less of foodgrains. More money is spent on non-food items and to the extent that rich people are not eating that much, the magnitude of foodgrains available for the poor people is all the greater. *(Interruptions)*...

SHRI N. E. BALARAM : I think you might have read Gadgil's report about the Fourth Five Year Plan and how he criticised and how he pooh-poohed the trickle-dowa theory. I do not want to say more than that. Your economists have been arguing about the trickle down theory and that is what you have been repeating in the House and this has been pooh-poohed by Prof. Gadgil. Thereafter you have thought about introducing the anti-proverty programme. Do you forget that ? That is what I am asking from you. I am questioning the main thrust of your economic plan. The main thrust of your economic plan was to produce more consumer durables for upper classes. That is why you have produced a big network of TV throughout the country. That is what we are facing now. I am not against the spread of TV. But what is the net result, I ask ? Now, what was our TV doing ? Instead of improving... *(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY): Please listen to him. He is presenting his view-point. He is presenting his side of the picture.

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV (Maharashtra) : Sir, in 1979-80, when our party came to power, the foodgrains production

[Shri Vithalrao Madhavrao Jadhav]

of the country was 120 million tons and when we left the Government, it was 175 million tons. It is an achievement of the Congress Party Government. You should remember this thing.

SHRI N.E. BALARAM : I never deny the fact that there was an increase in foodgrains production in the last few years.

I do not deny that. We have to discuss other things also in the context of the Budget. Are you contesting my main point ? My main point is, the main thrust of your Plan was the production of more durable consumer goods and you know what we are spreading through

the TV now. Are we utilising the TV to spread the message of unity of our country, to raise the awareness of the common people against the dangers of the country? What are we spreading in the TV ? We are spreading throung the TV brand consciousness about these durable consumer goods. If you make a study, you will find that for the last five years, the part of the national income coming from the advertising industry has increased six times because of this. *(Interruptions)* I am saying that if the present Government also go in the same way, with the same brand consciousness propaganda, I think they will be in the soup, in difficulty. That is what I am saying. Why did the people reject you ? Why did the people give verdict against you ? It was because of your policies. The net result of your TV was that through the TV, they were spreading brand consciousness. Even a child will say, Palmolive, Palmolive. What is it ? It is called the brand consciousness. It has been condemned by all the scientists in the world. That is what your TV has been doing for so many years. Don't talk of the new economic policy. I say nothing more about it than that. Professor Chandresh P. Thakur raised a relevant point. I will reply when I get a chance at the time of Budget discussion. Now, the second thing was education. What happened to the Educational Policy ? What is the percentage of literacy now in the country ? Where are we now ? How much we have improved ? What improvement is there ? Nothing. There is no substantial improvement. How many primary schools are there ? The condition is very poor in the country. We are ashamed to say that even today in many areas, people do not know how to write and how to read. There are a large number of villages like that. What has the education policy achieved? We know the achievements of the New Education Policy, the New Economic Policy, the New Textile Policy, etc. I do not want to take much time. There has been a fiasco. They have not improved either the economy or the culture or anything in the country. On the contrary, they have created numerous problems for the country, for our people. That is what I am saying. There must be some self-assessment on our part.

Now, I would like to say one more thing before I conclude my speech. This Government is trying to restore the democratic traditions of our country which were slowly disappearing for the last ten years, especially for the last five years. I do not think anybody will question my statement because all of us know. *(Interruptions)*.

PROF. CHANDRESH P. THAKUR : I question.

SHRI N. E. BALARAM : If you question, you convince me that it is wrong. We are debating with you. *(Interruptions)*. The first thing is, this Government wants debates, meaningful debates. There are two types of debates. This Government wants meaningful debates. Whatever good things you are suggesting, we will accept, we will not reject. This Government is trying to restore some of the lost democratic principles. *(Interruptions)*

For instance, there is the Lok Pal Bill. We are going to discuss it. What is the intention, what is the approach there ? There was a sort of cynicism developing inside the country, from top to bottom. There were corruption charges against the Prime Minister too. Corruption had become the order of the day. How to get rid of these things ? They are introducing the Lok Pal Bill. I think it will create some confidence among the people. If you properly debate, arrive at a consensus on the Bill and implement it in the country, you can create confidence among the people and go ahead. *{Interruptions).*

SHRI H. HANUMANTHAPPA (Karnataka) : Please yield for a minute. We have already seen how the Lok Pal has functioned under the Janata Dal Government in Karnataka. *(Interruptions).*

SHRI N. E. BALARAM : I do not want to answer because he is my freind.

Now they are thinking of changing the Postal Bill. Do you know what it contains ? When the Bill comes you can see. Don't forget that all of you were supporting the most atrocious Defamation Bill. Your mind, mood, everything was spoiled. The entire democratic consciousness in the Congress party was spoiled at that time. Ultimately, the whole consciousness of the country rose like one man and so you were forced to withdraw it. But the mood was such in your party. Can you imagine a party existing in the woild without having inner party elections for seventeen years ? This is one of tho wonders of the world. A party is existing in the world without inner party elections for seventeen years. There is no democratic sense developing. it would take some time, according to me., for it to develop in your party. This is the best opportunity for that. Now they are introducing the Postal Bill. They are introducing a Bill, the Prasar Bharati Bill. Somebody was saying that the television was used for BJP purposes or Shiv Ssna Purposes. If that is so, I do not agree with that, I am totally agninstit. How we can do it ?

PROF. CHANDRESH P. THAKUR : What type of democracy is there in the Communist Party ?

THE VICE-CHAIRMAN (DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY) : We arc not discussing it now. Wc can discus? it privately.

SHRI N. E. BALARAM : 1 can give you a fecret now. About 200 Congress workers arc going to join my party the day after tomorrow in Kerala or in some other state... *(Interruptions)...* 1 do not want t© mention the place now.

SHRI V. NARAYANASAMY: This is your imagination.

THE VICE-CHAIRMAN (Dr. G. VIJAYA MOHAN REDDY Don't reply.

SHRI N. E. BALARAM : I do not want to reply. What I am saying is that the Prasar Bharati Bill may bo imperfect. It requires some amendment, I agree. But how can we control it ? How can we control, "wo" meaning the people the representatives of the people ? I do

[Shri N. E. Balaram]

not want to say anything about the last Government. How it was misutiliscd ! It was terrible. Somebody was telling that he did not want to open the television because he was forced to sec one man's picture every time. Even people go to see the most beautiful picute, the picture of Sri Krishna, the picture of Balakrishna only once a day. It is the most beautiful picture in the world. It is the most beautiful picture to look at, but even thet is seen by the people cither early in the morning or in the evening, once in a day. Not every time. They don't like it. On the television, we. were forced to see 24 hours the picture of a man, a single man. What an unfortunate situation in the country! Sir, let us have a new thinking about it. They arc introducing the Bill. Do you think that the Bill is intended to misuse by this Government? You can change it. We will accept it. My point is, wc want to restore, this Government wants to restore the democratic traditions in this country. By way of discussion and by reviving the democratic institutions, we are going to introduce the Bill. 1 would like to make only one request before I conclude my speech. The point is.. .*(Interruptions)*... I know we have differences; otherwise I would not have joined this parly. Let us debate. My one request is... *(Interruptions)*... I was there. You know, my last speech in the AICC Session was in 1939. I am saying that I was there and afterwards I said good-bye,.My one request to the Government is, they have mentioned that all the land legislations will be put in the Ninth Schedule. It is a very good thing that all the land legislations should be kept in the Ninth Schedule. Not only tha*, in a number of States the Agrarian Reforms Bills arc not even introduced. Take for instance what is happening in Bihar. What is, the root cause of vilenco in Bihar ? What is the root cause of boothcapturing in Bihar ? What is the root cause for the killing of a large number of agricultural workers in Bihar ? What is the need for organising such Senas. I would like to ask these questions. I am not asking you ; I am asking myself only.

SHRI V. NARAYANASAMY : What happened in Meham ? ... *(Interruptions)*...

SHRI S. S. AHLUWALIA (Bihar) : What happened inMcham? . .*(Interruptions)*...

SHRI N. E. BALARAM : I am making a point and you arc not following what I am saying. Some people cannot understand whatever others say. What can I do ? ... *(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (Dr. G. VIJAYA MOHAN REDDY) : You don't listen to them. You just speak.

SHRI N.E. BALARAM : There is a saying in Sanskrit. ,

I will give the English rendering of it . If one is ignorant, one can be taught easily. An ignorant man can bs taught easily. If a person is a scholar, he can be taught much more easily. But, in between, there is a set of people. They know something and they do not know anything else. What can you do about these people ? You cannot do anything at all ... *(Interruptions)*.. Even Brahma cannot do anything and even Brahma cannot teach them. You are also that set of people. What shall I do ? Nobody can teach you. That is the position now *(Interruptions)* ...

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV (Maharashtra): You think you know everything? ...*{Interruptions)*...

SHRI N. E. BALARAM tnis is not what I am saying. Thk ,?as written by Bartrihari and not fy *ran* ... *{Interruptions)*...

SHRI S. S. AHLUWALIA: It applies to you also ... *{Interruptions)* ...

SHRI N. E. BALARAM: What I am saying is that we should implement th": land legislation. Thay should implement as early as possible the land legislation throughout the.country. That is what is now required. In the past, it was neglected, terribly neglected, with tnc result that the landlords arc holding the countryside today and a largo number of movements are taking place. We know what they want. This is my request.

I see the new approaches and the changes in this and I think we will have sufficient discussion on these thing9 and the President's Address has given us an opportunity for that and I fully second the Motion moved by Shri Virendra Verma.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY): Now,thore are 83 amendments which are to be moved. Now, Dr. Ratnakar Pandey.

DR. RATNAKAR PANDEY (Uttar Pradesh): Sir, 1 beg to move :

1. That at the end ofthe Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not condemn the Government's decision to diastically scale down the security arrangements for Shri Rajiv Gandhi".

2. That at the end of the Motion the following b; added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the failur of thft Central Government to curb the activities of anti-national and secessionist forces in Punjab and Jammu & Kashmir."

3. That at the end ofthe Motion the following bs added, namely:—

"but regret that the Address does not mention the steps proposeo to *be* taken by the Government to solve the Punjab and Kashmir problems".

4. That at the end of the Motion, the following *bs* added , namely:—

"but regret that the Address docs not contain any concrete steps to solve the Ramjanambhoomi Babri Masjid dispute."

5. That at t he end of t he Motion, the following be added , namely:—

"but regret that the Address does not condemn the failure of th« Government to curb violence in the recent Assembly elections, especially in Bihar and Haryana"

6. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not condemn the Haryana Government for its alleged role in the Meham Assembly poll in Haryana recently."

7. That at the end of the Motion, the following be added, nemely:—

"but regret that the Address docs not mention about the steps the Government propose to tak« to solve the unemployment problem in the country".

8. That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address docs not contain any indication of the Government's resolve to

[Dr. Ratnakar Pandey]

ameliorate the lot of woman folk in the country".

9. That at theend ofthe Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not refer to the steps the Government propose to take to arrest the rise in prices of essential commodities."

10. That at the end ofthe Motion, **the** following be added, namely:—

"but regret that the Address docs not mention any steps proposed to be taken by the Government to propagate the use of Hindi for official use throughout the country".

THE VICE-CHAIRMAN (DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY): Mr. Kulkarni. Not here. Yes, Mr. Bhandare.

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE (Maharashtra): Sir, I big to move:

14. That at the end ofthe Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the unconstitutional and impolitic dissolution of the Jammu & Kashmir Legislative Assembly by the Governor of Jammu & Kashmir."

15. That at theend ofthe Motion **the** following be added, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the failure of the Central Goyernmmt to curb the activities of anti national secessionist forces in Punjab and Jammu *&* Kashmir."

16. That at theend ofthe Motion **the** following be added, namely:—

"but regret that the Addrass docs not mention about th; steps proposed to *bi* talon by thi Govc,rnm;nt to solvo the Punjab & Kashmir problems."

17. That at thoend of th) Motion the following b; added, nanuly:—

"but regret that the Address does not nvmtion about thi steps the Govcrnhicnt propose to take against rising cost of essmtial commodities."

18. That at the end ofthe Motion the following ba added, namely:—

"but regret that the Addnss does not mention about the stop; proposed to bo taken to prevent abuse and exploitation of the girl child in the current International Year of the Girl Child."

29. That at theend ofthe Motion the following be added namely:—

"but regret that the Address does not mention that the Government's action in calling for *en masse* resignations of the Governors of all the States has devalued the high constitutional office of the Governor".

30. That at theend ofthe Motion the following be added, namely.—

"but regret that the Address does not mention that complete and comprehensive economic sanctions should be imposed against the South African regime for early dismantling of apartheid.

THE VICE-CHAIRMAN (DR: G. VIJAYA MOHAN REDDY): Now Mr. Bansal.

SHRl PAWAN KUMAR BANSAL (Punjab): Sir, I beg to move.

19. The at the end ofthe Motion the following b; added, namely:—

"but regrrt that the Address does not admit ofthe Governments

abject failure in tackling the explosive situation in Kashmir Valley which has deteriorated alarmingly during the last fovr months and poses a veritable threat to the nation's unity and integrity".

2Q. That at the end ofthe Motion ic following be added, namely:—

"but regret that the Address does not spell out the perception of the Government on the Punjab issue, its policy thereon and the action plan to deal with the same".

21. That at the end ofthe Motion tie following bs added, namely:—

"but regret that th? Address does not refer to the largn-scale violence unleashed and booth capturing and rigging perpetrated with the connivanes of the State machinery during the recent by-election to the Meham Constituency of Haryana Leigslative Assembly." .

22, That at the end of the vlotion, the following be added, lamely:-

"but regret that the Address does not refer to the blow inflicted on the ind spend snee of judiciary by the action of the Government in holding back the appointments of Judges which were finalised by the last Government and to give effect to which only Presidential orders were to be issued."

23. That at thcend ofthe Motion the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not admit ofthe low priority accorded by the Government to education."

THE VICE-CHAIRMAN (DR. G.VIJAYA MOHAN REDDY): Now, Mr. Kapil vcrma.

SHRI KAPIL VERMA (Uttar Pradesh): Sir, 1 beg to move:

24. That at the end ofthe Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address docs not contain any specific action plan to meet effectively and speedily the grave situation prevailing in Jammu & Kashmir."

25. That at the end ofthe Motion the following bo added, namely:—

"but regret that the Address, while referring to the formation of about a dozen Committees to deal wit h vital problems facing the nation, singularly fails, to outline any carefully formulated policy and mechanism to solve them."

26. That at the end ofthe Motion, the following ba added, namely:—

"but regret that the Address taking into account the astounding changes in East Europe, Soviet Union and South Africa, does not contain any fresh approach in foreign policy."

27. That at theend ofthe Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not refer to the brutal repression of the people fighting for democracy in Nepal and to the large-scale violation of human rights in that country."

28. That at theend ofthe Motion the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not refer to the shocking happenings in Meham Assembly by-election in Haryana and also to the fact that a number of candidates with criminal record have been elected to the State assemblies in the recent election."

THE VICE-CHAIRMAN (DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY): Now, Mr. Santosh Bagrodia.

SHRI SANTOSH BAGRODIA (Rajasthan): Sir, I beg to move; :

31. That at thoend of tb/5 Motion, the following bo added, nanwly:—

"but regret that the Address does not specify any policy for eradication of black money."

32. That at theend ofthe Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Aodress does not mention about the terrorist and underground activities in the State of Assam."

33. That at theend ofthe Motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address does not metion about the terrorist and naxalite activities in the State of Andhra Pradesh, which have increased during the last few years"

THE VICE-CHAIRMAN (DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY): Yes, Mr. Ahluwalia.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया (बिहार): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

34. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पिछली सरकार द्वारा अपनाई जा रही उन गतिशील नीतियों को स्वीकार नहीं किया गया है जिनके परिणामस्वरूप विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महान सफलता मिली है।"

35. प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पंचायती राज को भारतीय संविधान के अधीन सांविधिक दर्जा दिए जाने के लिए किसी ठोस कदम का उल्लेख नहीं किया गया है।"

36. प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आम आदमी पर आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतों के दबाव को स्वीकार नहीं किया गया है और इस प्रवृत्ति को नियंत्रित करने तथा कीमतों को कम करने के लिए किसी कदम का उल्लेख नहीं किया गया है।"

37. प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में चकमा आदिवासियों और बांग्ला देश में अल्पसंख्यकों पर किए जा रहे अत्याचारों और चकमाओं और हिन्दुओं के बड़ी संख्या में इस देश में आने से भारत को पेश आ रही समस्याओं का उल्लेख नहीं किया गया है।"

38. प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में फ्रांस और अन्य यूरोपीय देशों को, जिनके काफ़ी व्यापारिक हित भारत के साथ जुड़े हैं, पाकिस्तान परमाणु कार्यक्रम में उसकी मदद करने, जिससे इस क्षेत्र में तनाव बढ़ेगा, से रोकने के सरकार के संकल्प का उल्लेख नहीं किया गया है।"

39. प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में न तो पंजाब और जम्मू और काश्मीर में राष्ट्रविरोधी ताकतों द्वारा आतंकवाद और विध्वंस की बढ़ती हुई गतिविधियों की भर्त्सना की गई है और न इस प्रकार की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए किन्हीं ठोस कदमों का सुझाव दिया गया है।"

40. प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में न तो हाल के चुनावों के दौरान कट्टर-पंथियों के बढ़ते हुए प्रभाव की भर्त्सना की गई है और न देश में धर्मनिरपेक्षता के आदर्शों को मजबूत बनाने के सरकार के संकल्प का प्रतिज्ञान किया गया है।"

41. प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में न तो "मूल्यों पर आधारित राजनीति" चलाने के सरकार के संकल्प को दोहराया गया है और न ही निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव के रद्द कर दिये जाने के बावजूद मेहम विधान सभा उपचुनाव में मतदान प्रक्रिया का दमन करने में हरियाणा सरकार की भूमिका की भर्त्सना की गई है ।"

THE VICE-CHAIRMAN (DR. G.VIJAYA MOHAN REDDY): Now, Mr. Vishvjit P. Singh.

SHRI VISHVJIT P. SINGH Maharashtra): Sir, I h:g to move:

42. That at the end of the Mo tion, the following be added, namely: —

"but regret that the Address, while mentioning the situation in Jammu & Kashmir, does not refer to the sharp deterioration in the Law and order situation in the State since the 20th January, 1990."

43. That ;X the end of the Mo tion, the following be added, namely:—

"but regret that the. Address, while mentioning the situation in Jammu & Kashmir, does not clarify the stand of th" Government on the retention of Article 370 ofthe Constitution of lndia."

44. That at the end of the Mo tion, the following be added, na mely :—

"but regret that the Address does not mention a specific time-frame for arriving at a solution of the Ram Janam-bhoomi-Babri Masjid dispute."

45. That at the end of the Mo tion, the following be added, na mely :-

"but regret that the Address, while mentioning defence pre-paredness , fails to clarify the stand of the Government about the Nuclear Option"

46. That at the end of the Mo tion, the following be added, na mely—

"but regret that the Address, while mentioning democratic institutions, fails to make any mention of the *en masse* dis-missal of Governors and Ambas-sadors and their replacement by committed political appointees of the present Government."

47. That at the end of the Mo tion, the following be added, na mely :—

"but regret that the Address, while mentioning the placing of some Land Reform Laws in the Ninth Schedule of the Consti-tution, does not clearly affirm the earlier commitment of the Government to include all Land Reform Laws in the Ninth Schedule ofthe Constitution."

48. That at the end of the Mo tion, the following be added, na mely :—

"but regret that he Address fails to mention that the interim relief to be paid to the Bhopa gas victims will be doled ou in meagre monthly instalment!

spread over three years and adjusted against the final amounts awarded."

49. That at the end of the Mo tion, the following be added, namely:

"but regret that the Address fails to mention the hostile stand taken by Bangladesh vis-a-vis Kashmir."

50. That at the end of the Mo tion, the following be added, na mely:—

"but regret that the Address fails to take note of the democratic aspirations of the people of Nepal."

51. That at the end of the Mo tion, the following be added, na mely:—

"but regret that the Address, while mentioning the Indo-Sri Lanka Accord, fails to make a firm commitment regarding the secrity of the Tamil population and the devolution of powers to the North-Eastern provinces of Sri Lanka."

52. That at the end of the Mo tion, the following be added, na-' mely :—

"but regret the Address, while mentioning our relations with the United States of America, fails to clarify our stand on the outstanding issue of our Patents Law."

53. That at the end of the Mo tion, the following be added, na mely:—

"but regret that the Address fails to mention the signal contribution of India under the leadership of late Smt. Indira Gandhi and Shri Rajiv Gandhi towards the independence of Namibia."

VICE-CHAIRMAN (DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY) : Yes, Mr. Narayanasamy.

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Sir, I beg to move:

54. That at the end of the Motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address does not refer to the deteriorating law and order situation prc-. vailing in Jammu & Kashmir where the civil administration has been taken over by the militants and the Government has no control over the administration at all and there is large scale migration of minorities from that State to other States and Pakistan is openly aiding and abetting the tcrrorits and the Government has totally failed to restore normalacy in the State."

55. That at the end of the Mo tion, the following be added, na mely :—

"but regret that the Address does not refer to continuing violence and killing of innocent people by terrorists in Punjab and the failure of the Government to hold Assembly elections in that State to start the political process and to hand over the administration to the elected representatives."

56. That at the end of the Mo tion, the following be added, na mely:—

"but regret that the Address does not mention about violence,

booth-capturing and killing of p?ople in recent Assembly etrc-tions in Bihar and also in Mcham constituency of Haryana thereby subverting the democratic process of election and encouraging money and muscle power by the Government."

57. That at the end of the Mo tion, the following be added, na mely:—

"but regret that the Address docs not refer to the suppression of press freedom by the present Government in various States, especially in Jammu & Kashmir, after the imposition of President's Rule."

58. That at the end of the Mo tion, the following, be added, na mely :—

"but regret that the Address docs not refer to the National Front Government's failure to control the rise in prices of essen-tial commodities and large scale bungling in the public distribu-tion system."

59. That at the end of the Mo tion, the following be added, na mely:—

"but regret that the Address does not refer to the Government's failure to settle the long pending Cauvery water dispute between the Governments of Karnataka, Tamil Nadu and Pondicherry and to solve the problems faced by the farmers in these regions."

60. That at he end of the Mo-ion, the following b: added, na mely:—

"but regret that the Address does not refer to the Govern-ment's failure to implement the loan waiver scheme thereby ne-gating the announcement made by the Primn Minister and the Finance Minister to waive loans to the farming community."

61. That at end of the Motion, the following be a added, na mely:—

"but regret that the Address dots not refer to the steps taken by the Government for the safety and security of the Tamils living in Sri Lanka after the withdrawal ofthe IPKF from there."

62. That at the end of the Mo tion, the following the added, na mely:—

"but regret that the Address does not condemn the involve-ment of Pakistan in the internal affairs of India by aiding and abetting the terrorists in Punjab and Jammu & Kashmir."

THE VICE-CHAIRMAN (DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY) : Mr. Subramanian Swamy, Not here. Shri Ram Naresh Yadav. Not here. Yes, Mr. Salaria.

SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA (Jammu and Kashmir) : Sir, I beg to move :

75. That at the end of the Motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address does not mention the develop-ments following the appointment of Shri Jagmohan as Governor of Jammu & Kashmir, such as the imposition of Governor's Rule, dissolution of the Legislative Assembly and the atrocities on the people and long spells of curfew."

76.aThtat the end of the

[Shri Shabbir Ahmad Sa'aria]

motion the following be added, namely :—

"But regret that the Address does not indicate the time within which the democratic process in the State of Punjab will be restored and the election to the Legislative Assembly of that State will be held."

77. That at the end of the Motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address does not state that the decisionof the Court in Ramjanambhoomi - Babri Masjid dispute shall be followed."

78. That at the end of the Motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address does not state the time within which the recommendations of the Gujral Committee shall be implemented without which the assurance for the promotion of Urdu is a mere eye-wash."

79. That at the end of the Motion, the following be added, namely :—

"But regret that the Address does not assure that the recommendations ofthe Sarkaria Commission shall be adhered to and that all erosion in the autonomy ofthe State of Jammu & Kashmir shall be undone by restoration of 1952 position."

80. That at the end of the Motion, the follwing be added, namely :—

"but regret that the Address does not contain any assurance that pending the establishment of the high level judicial commission the appointment of High Court and Supreme Court judges shall not be made."

81. That at the end of the Motion, the following be added, namely :—

"but regret that there is no assurance in the Address to implement the recommendations of the Government of Jammu & Kashmir for conferring Scheduled Tribe status on Gujars, Bakarwal and Argons of that State.

82. That at the end of the Motion, the following be added, namely :—

"but regret that the Address does not mention the steps proposed to be taken to ensure that a female foetus is not destroyed by any clinical or other means."

83. That at the end of the Motion, the following be added, namely :—

"But regret that the Address does not mention the fact that l/3rd of the territory of the State of Jammu & Kashmir and l/3rd of its population have been separated for the last 43 years by the ceasefire line and that there are no means for the people of the State to move within the State."

The questions were proposed.

श्री मोर्जा इरशादबेग (गुजरात) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर रखे गए धन्यवाद के इस प्रस्ताव पर मैं अपना समर्थन व्यक्त नहीं कर सकता ।

मान्यवर, अभी लोक सभा का चुनाव हुआ और नई सरकार अस्तित्व में आई । नई सरकार ने देश के लोगों में यह कह कर मत मांगा था कि हम देश में परिवर्तन

लाना चाहते हैं । मान्यवर, परिवर्तन आया । परिवर्तन देश में यह आया है कि पहली बार कम मत मिलने वाले लोग मिले और उनकी सरकार प्रतिस्थापित हुई । सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते देश में यह परिवर्तन आया कि कांग्रेस ने यह स्वीकार किया कि देश की जनता ने जो निर्णय लिया है उस निर्णय के अनुसार जो भी सरकार प्रतिस्थापित होती है उसके सामने वह विरोधी दल की भूमिका निभाये । चुनाव के बाद जो सरकार में भागीदार बने और जिन्होंने सरकार बनाई उन लोगों ने देश के लोगों को जो वचन दिए थे, जो घोषणायें की थीं, देश की जनता यह मानकर चल रही थी कि जैसे ही इस सरकार की प्रतिस्थापना होगी वैसे ही जितनी भी घोषणायें की गई थी, उनके ढिंढोरे में, उनको अमल में लाया जाएगा । लेकिन मान्यवर, अफसोस है कि इस सरकार ने, सौ दिवस गुजर चुके हैं, लेकिन उसने कोई भी दिशा नहीं दिखाई है । कम से कम जो वायदे उन्होंने लोगों से किए थे, अपने चुनावी ढिंढोरे में जो बात कही थी उसमें से किसी एक को भी पूर्ण करने की दिशा में कोई भी कदम नहीं उठाया गया है । मान्यवर, प्रजातंत्र में सरकारें बदलती हैं । प्रजातन्त्र में लोगों को अपना अभिगमन दिखता है और अभिगम के पश्चात यहां पर किसी एक पार्टी की सरकार आती है । सरकारें आती हैं और जाती हैं । लेकिन जो भी सरकार प्रतिस्थापित होती है वह संविधान के अधीन होती है । संविधान में जो बातें बताई गई होती हैं वह उसके अधीन होती हैं । इस सरकार के सदस्यों को यह भी पता नहीं है कि वे सरकार में हैं । वे अब विरोधी दल में नहीं हैं । लेकिन क्योंकि मोर्चा बना और परिवर्तन आया । परिवर्तन, ऐसा आया कि जो एक दूसरे का मुंह देखने को तैयार नहीं थे, जिनके नेता एक साथ नहीं बैठ सकते थे, मिल सकते थे, ऐसे लोगों ने सरकार बनाई और दोनों ने मिलकर सरकार को समर्थन दिया । मान्यवर, सरकारें आती हैं और जाती हैं । लेकिन जिसको सरकार कहते हैं वह सरकार सम्पूर्ण समय के लिए देश में होती है । चाहे यह सरकार हो और चाहे यह सरकार हो । लेकिन उस सरकार के देश के साथ जो वायदे किए होते हैं, विदेशियों के साथ जो वायदे किए होते हैं उन वायदों को निभाना नई सरकार का परम कर्तव्य होता है । इस सरकार को यह भी पता नहीं है कि दूसरे देशों के साथ जो करार किए गए हैं और दूसरे देशों से जो हम सहायता लेने जा रहे हैं, उनके एक शब्द के कारण उसका क्या परिणाम हो सकता है । इनको यह पता नहीं है । मान्यवर, इन्होंने आते ही यह कहना शुरू कर दिया कि देश का खजाना खाली है । मैं कहना चाहता हूँ कि पिछली कांग्रेस सरकार के शासन में एक भी क्षण ऐसा नहीं आया जब कि हमने विदेशों से लिए ऋण की अदायगी में एक भी दिन का विलम्ब किया हो और हम डिफाल्टर रहे हों । जो आज सरकार में बैठे हैं उनको यह पता नहीं है कि कितनी ही सहायता बाहर के देशों से भी लेनी पड़ती है । आज विदेश में लोग कह रहे हैं कि जब सरकार का प्रधान मंत्री यह कह रहा है कि देश का खजाना खाली है तो फिर हमारा भुगतान कैसे होगा । इससे और सहायता देने के बारे में उन लोगों के मानस में एक संशय पैदा हो गया है । आप कम से कम यह समझ लें कि आप सरकार में बैठे हैं । आपको सरकार चलानी है । मान्यवर, आप आंकड़े देकर बताएं कि कहां खजाना खाली है । आप हमको बतलाइये । मान्यवर, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पेश किए गए धन्यवाद के प्रस्ताव पर जब विरोधी दल की ओर से सबसे पहला भाषण यहां पर हो रहा है तो मुझे खेद है कि मंत्रिमंडल का कोई सीनियर मैम्बर यहां पर बैठा हुआ नहीं है । मान्यवर, वचनों की कीमत होती है ।

मान्यवर, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, कि कम से कम हिन्दुस्तान की जो इज्जत अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में है इसको बनाए रखिए । दूसरे राष्ट्रों के साथ जो करार किए गए हैं वह करार सरकार के सरकार के साथ होते हैं और एक देश की जनता और दूसरे देश की जनता के साथ करार होता है । पिछली सरकार ने जो करार किए हैं आप उनको

[श्री मीर्जा ईर्शादबेग]

रिव्यीपन करना चाहते हैं इससे अन्तराष्ट्रीय बाजार में आपकी क्या कीमत रह जाएगी? मान्यवर, भूटान के साथ हमने हाइडल प्रोजेक्ट के बारे में करार किया है, उसको आप रिव्यीपन करना चाहते हैं। इससे कितनी बिजली हम उत्पन्न करना चाहते थे? आपकी इज्जत अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में क्या होगी? अगर आप दूसरे देशों के साथ करार करने जायेंगे आने वाले समय में आपकी क्या कीमत रह जायेगी कम से कम आप समझदारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ नेतृत्व कीजिए। थोड़ी सी समझदारी से चलिए। हमें तो अनुभव है और अनुभव के आधार पर हम बतायेंगे कि इस देश का विरोधी दल कैसा हो सकता है। जहां समर्थन की बात है उसे हमने राज्य सभा में मैंजोरिटी में रहते हुए भी समर्थन दिया है। हमने कहा है कि हम रचनात्मक सहयोग देंगे। मैंने सदन में आगाह किया था उन लोगों को हम से घबराने की जरूरत नहीं है लेकिन जिनका समर्थन ले कर बैठे हो इन लोगों को जरा गहराई में जा कर सोच लीजिए, समझ लीजिए। हम तो चाहते कि आपकी सरकार चलें, पूरे पांच साल तक आप चलाइये। पांच वर्ष के लिए पहले भी आपकी सरकार आई थी। हमने तो उसको नहीं तोड़ा था। वह सरकार अपने ही बोझ से टूटी थी। इसलिए ऐसे कार्यक्रम इस देश में चलाइये जो जनहित के कार्यक्रम हों। जरा भी जनहित का कहीं भी अवरोध किया गया तो कांग्रेस पार्टी इस राज्य सभा में और लोक सभा में डर कर उसका मुकाबला करेगी। मैं याद दिलाना चाहता हूँ जो नीति अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हम लेकर चले हैं हमारे देश की इज्जत उससे कई गुना ज्यादा बढ़ी है। मैं आपके माध्यम से याद दिलाना चाहता हूं राष्ट्र को जो नान-अलाइनमेंट की नीति हम ले कर चले थे उस नान-अलाइनमेंट की नीति के कारण पूरे विश्व में हम तीसरी सत्ता के रूप में स्थापित हुए। इसके लिए धन्यवाद दिया जाना चाहिए पंडित जवाहर लाल नेहरू को और उनके बाद आने वालों को इंदिरा जी को और राजीव गांधी जी को उन्होंने इस बात को समता से आगे बढ़ाया और पूरे विश्व में जनमत तैयार किया जो भारत के समर्थन में था। आज कितने दिन हुए हैं? 100 दिन और 100 दिन में अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजार मे आपने हिन्दुस्तान को कहां ला कर के खड़ा कर दिया है। आज के अखबार में विदेश मंत्री गुजराल जी का एक निवेदन छपा है। मेहरबानी कर के आप जिम्मेदारी से सरकार को चलाइये। इस किस्म का विदेश मंत्री का निवेदन छपा है नान-अलाइनमेंट के बारे मे कुछ राष्ट्रों के बारे में तो क्या कीमत रह जाएगी भारी अन्तर्राष्ट्रीय बजार मे? इसलिए मेहरबानी कर के जिम्मेदारी से सोच सोच कर चलिए कि आप सरकार में बैठे है। इतने ही दिनों में, 100 दिनों में यह बात हो गई। बड़े झूम झूम कर कह रहे थे कि इस सदन मे कह रहे थे बाहर कह रहे थे कि पड़ोसी राष्ट्रों के साथ कांग्रेस सरकार बड़े मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं बनाती रही है। अब 100 दिनों में कितने मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध आपने बना दिए। इस देश का दुर्भाग्य है कि एक विदेशी राष्ट्र का एम्बेसडर आ कर, उसका विदेश मंत्री आ कर इस देश की धरती पर आ कर इस देश के लोगों को गाली दे सकता है, इस देश के लोगों को धमकी दे सकता है, ईरान के साथ विष्टी करने के लिए हम किस को भेज रहे हैं? कम से कम आपको अन्तर्राष्ट्रीय लेवल की तुलना समझ कर आगे बढ़िए। इसलिए मैं आगाह करना चाहता हूं इतने वर्षों में हमने अपनी कीमत को अंतराष्ट्रीय बाजार मे खड़ा किया, एक दर्जा बना कर हम खड़े हुए हैं। कश्मीर का मामला आया। इस पर बड़ी बहस हो चुकी है। लेकिन कश्मीर के मामले में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में मैं पूछना चाहता हूं। पिछले 43 वर्षों में जब कांग्रेस का शासन था जो स्टेंड पिछले सालों में कुछ विदेशी सरकारों ने लिया है, इसके पूर्व लिया था। रूस से समर्थन करवाते हैं, दूसरे लोगों से समर्थन करवाते हैं। क्यों? कम से कम यह जिम्मेदारी आपने ली है तो इसका अहसास कराइये, अपने कार्यों से और अपनी नीतियों से। बड़ी मेहनत से इस देश की विदेश नीति हमने तैयार की है और विदेशों मे अपना नाम ऊंचा किया है।

इसलिए मेहरबानी करके, मैं आगाह करना चाहता हूं कि ऐसी नीतियां चलाइये जिनसे नान-एलाइमेंट मूवमेंट और ज्यादा अधिक सक्षम हों, मजबूत हो और कारगर बने और इस देश की हित रक्षा में आगे बढ़े ।

मान्यवर, वादे तो बड़े बड़े किये थे । आज वित्त मंत्री जी ने कह दिया। हम तो मान रहे थे जिस बात की चुनाव में आपने घोषणा की थी और जिस पर आपने लोगों का मत लिया था, जो आपने यह कहा कि हम किसानों के ऋणों को माफ करेंगे, इसमें बड़े किसान भी उन्होंने कहे थे, छोटे किसान भी कहे थे, सीमांत किसान भी कहे थे और आर्टीसन्स भी कहे थे लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहीं इसका इन्टीमेशन मुझे नहीं मिला । अब घुमा फिराकर, अपने वादे से हटकर आप स्माल फारमर्स और मार्जिनल फारमर्स तक लिमिटेड होना चाहते हैं ।... **(व्यवधान)**

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : (महाराष्ट्र) : मैंरा पांइट आफ आर्डर है। महोदय. देखिए इतनी इम्पार्टेंट बहस चल रही है और यहां कोई भी सीनियर मिनिस्टर हाउस में हाजिर नहीं है । राष्ट्रपति के अभिभाषण के बारे में इन लोगों की कितनी रुचि है यह इससे दिखता है ... **(व्यवधान)** प्राइम मिनिस्टर का कोई प्रतिनिधि होना चाहिए... **(व्यवधान)** इतनी महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है... **(व्यवधान)**

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : (बिहार) : यह राष्ट्रपति का अभिभाषण है...राष्ट्रपति के भाषण पर चर्चा सुनने के लिए प्राइम मिनिस्टर को उपस्थित रहना चाहिए ... **(व्यवधान)**

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (DR. RAJA RAMANNA) : Mr. Vice-Chairman, Sir, I would like to know what the definition of seniority is. There is nothing like that. There is no such definition of seniority. I am listening.

{Interruptions)

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL (Punjab) : By now he should have sent word to the Home Minister or somebody else.

{Interruptions)

DR. RAJA RAMANNA : Nothing doing.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : The way the Parliament is-being treated by the Ruling Party is bad. You also look at the number of their Members. Not more than 5 Members are there on the Treasury Benches. I do not want to raise a point regarding quorum. *{Interruptions)*

SHRI MIRZA IRSHADBAIG: This is the first speech on the Motion of Thanks on the President's Address.

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV : I would request the hon. Minister, through you, not to make a mockery of this House. Some senior Minister must be present here. He has to reply to this debate.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : उपसभाध्यक्ष महोदय, अभी अभी राज्य मंत्री जी ने कुछ अल्फाजों का प्रयोग किया है...

उपसभाध्यक्ष (डा जी विजय मोहन रेड्डी) : ठीक बोला है ।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : ठीक नहीं बोला है ... **(व्यवधान)** उन्होंने बोला है यह सब चलेगा Is it a dictatorship उन्होंने कहा है सब चलेगा ... **(व्यवधान)**

THE VICE-CHAIRMAN : **(DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY)** it is not a dictatorship.

THE LEADER OF THE HOUSE (SHRI M.S. GURUPADASWAMY): I appreciate your feelings. I always

maintain that no Minister and no Government should insult the House in any manner or individual Members. I had some urgent work. I went there. I have come back. If there is any feeling in your mind that a senior Minister is not present. I would like you to appreciate my problem. I had to go there urgently and I came back. I do not mean any insult to the House at all.

SHRI S. S. AHLUWALIA : It was done by your junior Minister. It is a very serious thing. He said: "Nothing doing".

(Interruptions

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : He should know what he has to say in Parliament as a Minister.

SHRI JAGESH DESAI (Maharaslra) : Sir, when there is a discussion on the President's Address and when the first speaker on this side speaks the convention is that .. .*(Inter ruptions)*... the Prime Minister is present. But, unfortunately, this time, even the Cabinet Minister is not present. Always, it is a conven tion in this House that when the first speaker from this side speaks on the President's Address, even the Prime Minister is present. That is the convention of the House.

SHRI M.S. GURUPADASWAMY : If there is convention, I mean to maintain the convention. I repeat what I said earlier. There is no motive in this at all. I have come back. I have taken note of your feelings.

(Interruptions)

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : Sir, with all humility, I have to say that the words used by the hon. Minister of State were 'nothing doing; the House will go.' He should know that he is talking to the Members of Parliament in the Parliament, not to his junior officers. *(Interriupons)*

SHRI V. GOPALSAMY (Tamil Nadu) : It is not un-parliamentary.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY) : You are all speaking without the permission of the Chair. *(Interruptions)*

SHRI M. S. GURUPADASWAMY : May I again say, please do not make an issue of these things ? After all, as Members " of Parliament, we have to be generous to each other. *(Interruptions)*

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : Sir, you please ask for the record and see what the hon. Minister of State said.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY) : that is all right...

SHRI S. S. AHLUWALIA : He should learn how to behave with the Members of Parliament. *(Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY) : Mirzasahib, please carry on.

श्री मीर्जा इशाक बेग : मान्यवर, इस सरकार ने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में और एक बात कही। (व्यवधान)

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : Sir, those words should be deleted.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY) No, no.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : What are you saying, Sir ? They are not to be deleted?

THE VICE-CHAIRMAN (DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY) What ?

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : If something was said which is not really to be said to the Members...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY) : I have been listening to him. There is nothing that has been said.. .*(Interruptions)*

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : Sir, you go through the record.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY) : Mirzasahib, please carry on.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY) : Already the Leader of the House has explained the matter satisfactorily. There is nothing unparliamentary. He was volunteering to give you the reply that he is attending to the work...

(Interruptions)

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : The question is as to what the Minister of State has said here. .

SHRI S. S AHLUWALIA Can he repeat his words ?

THE VICE-CHAIRMAN (DR. VIJAYA MOHAN REDDY) : Mirzasahib, carry on. *(Interruptions)*

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : Sir, I seek your protection. I have said something. Kindly do not overlook it and ask for the record.

SHRI S.S AHLUWALIA : We want your ruling on this. *(Interruptions)*

SHRT VISHVJIT P. SINGH (Maharashtra) : Mr. Vice-Chairman, Sir, I have the greatest respect for the hon. Mini ster of State. I know about his career, I know his background. I have great respect for him. But he is not familiar with the conventions of this House. As Mr. Gurupadaswamy, the hon. Leader of the House has just now said, the convention in this House is that when the first speakers are speaking, there is a senior Minister present. *(Interruptions)* One minute, please. That protest was lodged quite vehemently by our side. And in response, the hon. Minister of State with great annoyance said, "nothing doing."

THE VICE-CHAIRMAN (DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY) : No annoyance in that. Let us not infer something which is not intended.

SHRI VISHVJIT P. SINGH : He was annoyed and he said "nothing doing", and sat down. *(Interruptions)* All I have to say, Mr. Vice-Chairman, Sir, and my request to the hon. Minister of State through you is to say that he withdraws his remarks.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY) : No, no. We will go through the record.

6.00 P.M.

SHRI VISHVJIT P. SINGH : Why cannot he withdraw his remarks ? That will solve the problem.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY) : That is all right. You please carry on, Mirzasahib. *(Interruptions)*

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): Sir, we seek your protection. Please do not defend the Minister like that.

THE VICE-CHAIRMAN DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY) : It is not a question of dfending the Minister-----

(Interruptions)

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : We seek your protection. Please do no defend the Minister like that.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. G. VIJAYA MOHAN) REDDY) : No, no. *(Interruptions)*

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : We have all the respect and high esteem for the hon. Minister of State. But he must realize that we are functioning in the Parliament.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY) : That is all right, we will go through the records.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : What will you do after going through the records ? Please tell us. Just assure the House what you will do.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY) : You have asked that the record must be gone through and I have assured you that I will do it.

SHRI VISHVJIT P. SINGH : He has said nothing unparliamentary. There is no point in going through the records because he has said nothing unparliamentary

THE VICE-CHAIRMAN (DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY) : There the matter ends.

SHRI VISHVJIT P. SINGH : I am sorry, there the matter does not end. *(Interruptions);*

SHRI VITHALRAO MADHAV-RAO JADHAV : You go through the records and then decide. If these words are there, you delete them.

SHRI VISHVJIT P. SINGH : I appeal to the Leader ofthe House.

SHRI VITHALRAO MADHAV RAO JADHAV: You must go through the records.

THE VICE-CHAIRMAN (Dr. G. VIJAYA MOHAN REDDY) : Mr. Mizra, please proceed with your speech. *(Interruptions)*. I cannot say nothing more than this that I will go through the records.

DR. RAJA RAMMANA : Mr. Vice-Chairman, Sir, I did not really know that this is going to cause so much feeling of hurt to the hon. Member. Therefore, I withdraw what I said and I am sorry that it was done.

SHRI VISHVJIT P. SINGH) : Well spoken. Very good.

SHRI V. GOPALSAMY : Your colleague, yesterday, do you know how he behaved ? And you were keeping quiet.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY) : I have an announcement to make.

ANNOUNCEMENT RE: RECOMMENDATION OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

THE VICE-CHAIRMAN (DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY): I have to inform Members that the Business Advisory Committee at its meeting held today, the 15th March, 1990 recommended that the house should sit upto 8.00 p.m. today and from tomorrow, the 16th March, 1990, should sit upto